International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा पर प्रभाव : बिहार के जहानाबाद जिला का तुलनात्मक अध्ययन

सतीश कुमार[1], डॉ नागेश कुमार[2]

[1]शोधार्थी भूगोल विभाग पटना विश्वविद्यालय, पटना
[2]सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग बी एन कॉलेज, पटना

सारः
सर्व शिक्षा अभियान 2000–2001 में शुरू की गई प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य सभी को शिक्षा तक पहुँच, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में निचले पायदान पर है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन बिहार राज्य में हुआ है जिसका प्रभाव हमारे अध्ययन क्षेत्र जहानाबाद पर भी पड़ा है। अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें आँकड़ों संकलन, स्वयं निरीक्षण, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी पत्र–पत्रिकाएँ, असर रिपोर्ट, थेसिस का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र जहानाबाद में सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने से सफल नामांकन दर, साक्षरता दर, आधारभूत स्कूली सुविधाएँ, ड्रॉप आउट में कमी, लैंगिक अंतर का कम होना जैसे सकारात्मक प्रभाव देखे गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में 2000–2001 से वर्तमान समय तक आये परिवर्तन को विभिन्न आँकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तुलनात्म्क अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान का सकारात्मक प्रभाव जिला में देखने को मिला है।

कुंजी शब्द : सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता दर, ड्रॉप आउट, लैंगिक अंतर, शिक्षा, सार्वभौमिकरण

परिचय :
शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है जो न केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाती है बल्कि पूरे समाज तथा राष्ट्र को सामूहिक लाभ पहुँचाती है। प्रभावी शिक्षा प्रणाली से ही देश का विकास होता है। कोई भी राष्ट्र मानव पूँजी पर निवेश के बिना सतत् आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोच सकता, जो आर्थिक विकास के लिए एक इंजन का काम करती है। हालांकि यह एक दीर्घकालिक निवेश और धीमी प्रक्रिया है लेकिन शिक्षा आर्थिक विकास की ओर बढ़ने का एक तरीका है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता, रचनात्मकता को बढ़ाती है और तकनीकी उन्नत्ति को बढ़ावा देती है।
वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को पूरे देश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 06–04 वर्ष के बच्चें को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण भारत में बुनियादी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्न कर रही है। यह अभियान केन्द्र, राज्य और स्थानीय शासन की भागीदारी से संचालित है।

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य :

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल, शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षो की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष बल दिया गया हो, पर बल देना।
- स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक वर्ग क्षेत्र को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।

अध्ययन का उद्देश्यः
प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–
1ण सर्व शिक्षा अभियान के कारण साक्षरता, सकल नामांकन में आये परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2ण् सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से अध्ययन क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन जैसे– आधारभूत स्कूली सुविधाएँ, ड्रॉप आउट में कमी, लैंगिक अंतर का कम होना आदि का अध्ययन करना।

क्रियाविधि :

प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्राथमिक आँकड़ों तथा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के लिए स्वयं अवलोकन, साक्षात्कार एवं द्वितीयक आँकड़ों के लिए जनगणना रिपोर्ट, थेसिस, इंटरनेट, असर रिपोर्ट, पुस्तकों, पत्रिकाएँ का अध्ययन किया गया है।

साहित्य की समीक्षा :

मल्होत्रा, (2006), भारत के आठ राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम) में अध्ययन आयोजित करता है। इस लेख में यह दर्शाया गया है कि नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है विशेषकर भारत के पिछड़े राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 63 और 52 दर्ज की गयी है। इसके अलावे बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एकल शिक्षक अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है। सर्वेक्षण में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को शिक्षा प्रणाली विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में अधिक धन लगाना होगा।

दास (2007), सर्व शिक्षा अभियान के पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता और समस्याओं पर केन्द्रित अध्ययन किये है। उनका लेख शैक्षिक परिणामों जैसे– नामांकन अनुपात, ड्राप आउट अनुपात, प्रतिधारण अनुपात, बुनियादी सुविधाएँ, छात्र शिक्षक अनुपात आदि पर प्रकाश डालता है। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि बिहार, झारखण्ड और असम नामांकन अनुपात में अच्छा प्रदर्शन कर रहे है।

प्रकाश (2012), लेख बिहार की प्रारंभिक शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं और छात्रों के सीखने के कौशल के बारे में पता लगाया। उनकी खोज से पता चलता है कि अलग–अलग शौचालय की कमी के कारण शिक्षक और लड़कियाँ स्कूल आने से कतराते थे। इसके अलावे पीने की पानी की सुविधा एक और समस्या है। दूसरी ओर शिक्षक छात्र अनुपात भी बहुत अधिक है। छात्र के सीखने की क्षमता बहुत कम है।

कमल (2015), भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का पता लगाये हैं। उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और प्रति वर्ष वृद्धि दर 2.30 प्रतिशत है। इसके अलावे 1950–51 से 2013–14 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि भारत ने सार्वभौमिक पहुँच, नामांकन और प्रतिधारण लगभग प्राप्त कर लिया है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता निराशाजनक है। यह निष्कर्ष द्वितीय डाटा पर आधारित है जो कि एमएचआरडी रिपोर्ट 2013–14 से लिया गया है।

आडुकिया (2016), प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के महत्व पर जोर देता है। उनके अध्ययन में यह पाया गया है कि स्कूली शौचालयों की पहुँच का नामांकन अनुपात और ड्राप आउट अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि लिंग विशिष्ट शौचालयों का महिला नामांकन अनुपात पर अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर लिंग विशिष्ट शौचालयों से स्कूल में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।

टेक्सेरा और लोरेइरी (2019), ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अंतर स्कूल जाने की क्षमता को और प्रभावित करता है।

अध्ययन क्षेत्र :

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य का जहानाबाद जिला है। यह राजधानी पटना से सटा हुआ है जो जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। इस जिले की दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा क्रमशः गया, नालंदा, अरवल है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किमी० है। जहानाबाद जिले का आबादी 11.25 लाख (2011) है। इस जिले की प्रमुख नदी फल्गु, मोहना, दरधा, मोरहर आदि है। जिले का साक्षरता दर 66.80 प्रतिशत (2011, जनगणना) है। जनसंख्या घनत्व 1209 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

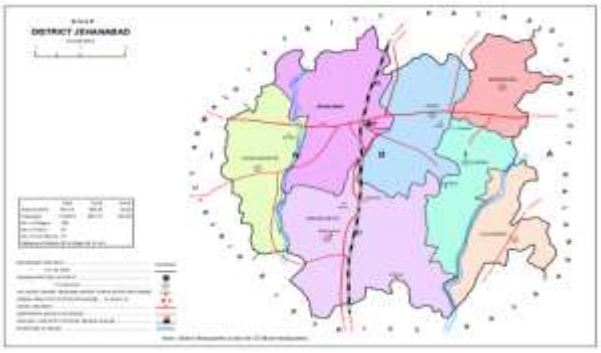

सर्व शिक्षा अभियान का शिक्षा पर प्रभाव :

बिहार के जहानाबाद जिला का तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण निम्नलिखित तथ्यों एवं आँकड़ों पर आधारित हैं–

विद्यालयों की संख्या :

विद्यालय शिक्षा का घर होता है। यदि विद्यालयों की संख्या पर्याप्त न हो तो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। जहानाबाद जिला में सर्व शिक्षा के क्रियान्वयन से विद्यालयों की संख्या बढ़ी जिसे नीचे के आँकड़ों में देखा जा सकता है।

वर्ष	जहानाबाद जिला में कुल विद्यायों की संख्या
2010–11	941
2013–14	981
2015–16	993
2021–2022	1092

स्त्रोत : यू डाइस तथा स्वयं संकलन।

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 2010–11 से (इससे पहले के आँकड़े अरवल जिले के साथ संलग्न होने के कारण उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। 2004–2005 से 2009–10 तक जहानाबाद और अरवल जिले के आँकड़ें एक साथ थे।) 2021–2022 तक विद्यालयों की संख्या में 151 की वृद्धि हुई जो लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

शिक्षकों की संख्या में परिवर्तन :

`सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की गयी है।

वर्ष	जहानाबाद में शिक्षकों की संख्या
2010–11	2673
2011–12	2937
2013–14	5910
2016–17	6501
2021–22	7164

स्त्रोत : यू डाइस तथा स्वयं संकलन।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जहानाबाद जिले में शिक्षकों की संख्या में 2010–11 से 2021–22 के बीच 4491 शिक्षकों की वृद्धि हुई है जो लगभग 168 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। बिहार में शिक्षकों की 582876 (2021-22, UDise Report) है। हाल में 2023–24 में लगभग 2.10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गयी जिससे बिहार में शिक्षकों की संख्या करीब 8 लाख हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र जहानाबाद में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव पठन–पाठन पर सकारात्मक हो रहा है।

छात्र शिक्षक अनुपात :

छात्र शिक्षक अनुपात को छात्रों की संख्या से शिक्षक की संख्या विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा की गुणवता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि कम संख्या में शिक्षक अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम नहीं हो सकते है। छात्र शिक्षक अनुपात कम होने का अर्थ नामांकित बच्चों के लिए कम शिक्षक उपलब्ध है जबकि कम छात्र शिक्षक अनुपात का अर्थ नामांकित बच्चों के लिए अधिक संख्या में शिक्षक उपलब्ध होने से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 निर्धारित करता है कि छात्र

शिक्षक अनुपात 30 : 1 होना चाहिए। जहानाबाद जिले में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित अनुपात के करीब 36 पहुँच गया है। यह आँकड़ा 2023–24 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया है जो बिहार के सभी जिलों में सबसे बेहतर है।

वर्ष	छात्र शिक्षक अनुपात
2010–11	55
2012–13	44
2013–14	40
2015–16	38
2023–24	36

स्त्रोत : यू डाइस, 2023–24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं स्वयं अवलोकन।

वहीं बिहार में यह अनुपात 52.3 है। सबसे निचले स्तर पर पूर्णिया है जहाँ यह अनुपात 70 है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण का स्तर बेहतर हुआ है। उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि छात्र शिक्षक अनुपात 2010–11 में 55 था जो 2023–24 में घटकर 36 हो गयी है।

स्कूली आधारभूत सुविधाओं में परिवर्तन :

इसके अंतर्गत पेय जल की सुविधा, कमरों की संख्या, शौचालय, बिजली, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, पुस्तके, खेल का मैदान, फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट की सुविधा इत्यादि को शामिल किया जाता है। किसी भी स्कूली की बुनियादी सुविधाएं इन्हीं चरों पर निर्भर करती है। अध्ययन क्षेत्र में जहानाबाद जिला में सर्व शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली आधारभूत सुविधाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़कियों के लिए शौचालय प्राथमिक विद्यालय में 2005–06 में 13.6 प्रतिशत थी जो 2021–22 में बढ़कर 97.99 प्रतिशत हो गयी है। प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल की सुविधा 74 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गयी है। बिजली की सुविधा प्रति स्कूल 20 प्रतिशत (2010–11) से बढ़कर 98.63 (2021–22) हो गयी है। रैम्प की सुविधा 48 प्रतिशत से बढ़कर 79.49 प्रतिशत हो गयी है। खेल का मैदान की सुविधा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अब भी बहुत कम 38.66 प्रतिशत (2021–22) है। कम्प्यूटर की सुविधा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1.2 प्रतिशत (2010–11) से बढ़कर 12.45 प्रतिशत (2021–22) हो गयी है। बिहार स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था काफी चिंताजनक है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इंटरनेट सुविधा भी स्कूलों में 9.7 प्रतिशत है जो काफी कम है। इसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों में स्मार्ड बोर्ड कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

साक्षरता दर में परिवर्तन :

भारतीय जनगणना अनुसार वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक हो किसी भाषा को पढ़, लिख और समझ सकता है साक्षर है। साक्षरता दर प्रति सौ व्यक्ति पर साक्षरों का प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर को बढ़ाने में सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वर्ष	जहानाबाद जिला		
	कुल साक्षरता दर (प्रतिशत में)	पुरूष साक्षरता दर (प्रतिशत में)	महिला साक्षारता दर (प्रतिशत में)
1991	45.83	63.11	26.81
2001	53.30	70.10	39.40
2011	66.80	77.60	55.01

स्त्रोत : भारत जनगणना, 1991, 2001, 2011

इस आँकड़ें से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से पूर्व 1991 से 2001 के बीच कुल साक्षरता दर में 7.47 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि 2001 से सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के बाद 2001 से 2011 के बीच में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा 15.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि इस अभियान के साथ बिहार सरकार की साईकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रोत्साहन राशि योजना ने भी साक्षरता दर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ड्राप आउट में परिवर्तन :

ड्राप आउट का अर्थ होता है अपनी पढ़ाई पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देना। ड्राप की दर सौ बच्चों में छोड़े गये स्कूली बच्चों का प्रतिशत होता है। जहानाबाद जिला में 2008–09 में ड्राप आउट रेट प्राथमिक विद्यालय में 13.3 प्रतिशत था (UDise, 2009) जो कि घटकर 2022–23 में प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्रतिशत तथा माध्यमिक विद्यालय में 20.89 प्रतिशत है (स्त्रोत– शिक्षा मंत्रालय, लोकसभा में उत्तर, 2023)।

उपर्युक्त ड्राप आउट में कमी के पीछे सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा आधारभूत स्कूली सुविधा को बढ़ाया जाना, कक्षा 8 तथा मुफ्त पोशाक वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण, सभी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि इत्यादि कारक जिम्मेवार है।

निष्कर्ष :

शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू किया गया 2001 में सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र बिहार के जहानाबाद जिला में उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन से सकारात्मक ज्ञात पड़ा है लेकिन गुणात्मक शिक्षा अध्ययन क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। आधारभूत सुविधाएँ तो बढ़ी है लेकिन अभी गुणात्मक सुधार को लेकर काम बाकी है। दक्षिण के राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में गुणात्मक शिक्षा में काफी पीछे दिखाई पड़ता है। ये बाते असर की वार्षिक रिपोर्ट से भी पता चलता है। अतः केन्द्र के साथ राज्य को भी इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल में हुई शिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान को सफल और गुणात्मक शिक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

संदर्भ–सूची :

1ण दास (2007), सर्व शिक्षा अभियान में हम कितने आगे?
2ण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2023–24।
3ण भारत जनगणना, 1991, 2001, 2011।
4ण यू डाइस रिपोर्ट, विभिन्न वर्ष।
5ण समग्र शिक्षा रिपोर्ट कार्ड, अरूण सी. मेहता।
6ण एलीमेन्ट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड अलग–अलग वर्षो का।
7ण असर रिपोर्ट, 2022।
8ण प्रकाश एन., (2012), बिहार में शिक्षा : अभी भी एक लम्बी राह बाकी।
9ण डिस्ट्रीक्ट सेंसर हैण्डबुक – जहानाबाद, 2011, गुगल मैप, इंटरनेट।